पर्यावरण कानूनों का पालन जरूरी : पीएम

वरिष्ठ संवाददाता ॥ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों का पालन सभी को करना होगा। लेकिन इसका मतलब लाइसेंस परमिट राज की वापसी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने यह बात गुरुवार को दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन-2011 का उद्घाटन करते हुए कही। हाल में ही कुछ परियोजनाओं के मामले में नरमी के बावजूद उन्होंने कहा कि वह 'प्रदूषण फैलाने वालों से कीमत वसूलने' के सिद्धांत से सहमत हैं। वैसे इस सिद्धांत को लागू करने में कई बार दिक्कतें भी आती हैं। उन्होंने कहा कि नियम-कानून बनाना ही काफी नहीं है। उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्राध्यक्ष लियोनेल फर्नांडिस और सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री को सस्टेनेबल डिवेलपमेंट लीडरशिप अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मनमोहन ने कहा कि औद्योगिक देशों को उत्सर्जन कम करने के मामले में अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहिर करनी होगी। उन्हें कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन में तय की गई सीमा पर उत्सर्जन को लाना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें औद्योगिक देशों से इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने विकसित देशों से अपील की कि वे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद करें।

मनमोहन ने कहा कि भारत, चीन और दूसरे कई विकासशील देशों ने उत्सर्जन में कमी करने के लिए खुद लक्ष्य तय किए हैं और योजनाएं बनाई हैं। भारत अगर अपना पूरा ग्रीनहाउस उत्सर्जन रोक दे तो भी उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता।